RAJYA SABHA

Friday the 18th March, 1983/27th Phalguna, 1904 (Saka)

The House met at eleven of the clock, **Mr. Chairman** in the Chair.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Construction of Flyovers in Delhi

*281. SHRI RAMANAND YADAV:†
SHRIMATI AMARJIT KAUR:

Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether Government have drawn up any plan to construct more flyovers in Delhi to relieve congestion on the roads and to allow smooth flow of traffic;

(b) whether Government propose to construct a flyover on the Rohtak Road near Zakhira in Delhi, where a serious accident took place last year; and

(c) if the answer to part (b) above be in the negative, what are the reasons therefor and what are the details of the plans drawn up so far for construction of flyovers in Delhi?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI Z. R. ANSARI): (a) to (c) According to information received from the three agencies handling roads in the Union Territory of Delhi, while New Delhi Municipal Committee have no proposal for construction of any flyover at present, the Municipal Corporation of Delhi proposes to construct a flyover at Zakhira and also contemplates to undertake two more flyovers at Shakti Nagar and G.T. Road over Shahadra-Saharanpur Railway line. The first project stands sanctioned whereas the other two projects are in initial stages of planning. The Delhi Administration has only one proposal of a flyover across the road over bridge No. 22 on the Outer Ring Road near Okhla which is in an advanced stage of planning.

†The question was actually asked on the floor of the House by Shri Ramanand Yadav.

श्री रामानन्द यादव : सभापति जी, दिल्ली की आबादी बहुत ही तीव्रगति से बढ़ी है । लोगों के पास जो आवागमन के साधन होते हैं द्रुतगति से चलने वाले जैसे मोटर, स्कूटर, थ्री ह्वीलर्स उनकी भी संख्या काफी बढ़ी है । जिस मात्रा में लोगों की आबादी बढ़ रही है, कारें बढ़ रही हैं, सड़कों पर भीड़ बढ़ रही है उस मात्रा में दिल्ली में अधिक सड़कें नहीं बनाई जा रही हैं, न फ्लाईओवर बनाये जा रहे हैं और न कोई दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के पास इस भीड को केटर करने के लिए कोई दूरगामी योजना है । मैं आपके सामने एक छोटा सा उदाहरण देता हूं । 1980 में रोड एक्सीडेंट्स हुए थे 4313 जिसमें 840 लोग मरे थे और जो इंजर्ड हुए थे उनकी संख्या 3809 थी । फिर देखिए किस तरह से यह संख्या बढी है । सन् 81 में 4409 एक्सीडेंट्स हुए जिसमें 1051 मर गये और 3782 इंजर्ड हुए । सन् 82 में एक्सीडेंट्स की संख्या 4867 हो गई उसमें 1218 लोग मरे और 4404 इंजर्ड हुए । सन् 83 में अभी मार्च महीने तक 646 घटनाएं हुई हैं जिनमें 141 आदमी मर गये और इंजर्ड का आंकड़ा इनका ठीक नहीं है । मेरा ऐसा अनुमान है । इस तरह से घटनाएं बढ़ रही हैं और दिल्ली की बढती हुई आबादी को केटर करने के लिए जो इन्होंने दिया है उससे फ्लाईओवर्स के बारे में कुछ स्पष्ट नहीं हैं । सभापति महोदय, ऐसा लगता है कि जो लोग दफ्तर आते हैं उनकी संख्या बढ़ती जाती है । दिल्ली में ही भारत सरकार के सारे दफ्तर मौजूद हैं,

चाहे आयल एक्सप्लोरेशन बाम्बे हाई में हो तो बम्बई में वह दफ्तर नहीं होगा। देहरादून में होगा या दूसरी जगह होगा। अधिकांश स्टील मिल्स ईस्टर्न रीजन में लोकेटेड हैं लेकिन उनका हेड आफिस दिल्ली में बनेगा। आबादी इस तरह से बढ़ती जा रही है।

श्री सभापति : आप थोड़ा फ्लाईओवर्स के बारे में पूछिए।

श्री रामानन्द यादव : मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं, हालांकि यह सराहनीय है कि आपने फ्लाईओवर्स के निर्माण के बारे में विचार किया है। दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन भी एक पर विचार कर रहा है और आपने तीन और योजनाएं जो बनाई हैं उनका एस्टीमेट वगैरह बन गया है। यह सराहनीय कदम है इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन जितनी आबादी बढ़ रही है और जितनी आवश्यकता है क्योंकि दिल्ली में इण्टरनेशनल कान्फ्रेंसेज भी होती हैं, तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए क्या आप दिल्ली की आबादी को आवागमन की सुविधा देने के लिए और अधिक फ्लाईओवर और सड़कों के निर्माण के सम्बन्ध में विचार करेंगे ?

श्री जैड० आर० अन्सारी : जानने वाला हमारा तो जी यही चाहता है कि सारी दिल्ली में . . .

श्री उपसभापति : फ्लाईओवर्स ही फ्लाईओवर्स हों।

श्री जैड० आर० अंसारी : फ्लाईओवर्स का जाल बिछा दिया जाये। यादव जी ने जैसा इशारा किया यह बात सही है कि एक्सीडेंट्स की तादाद बढ़ी है और यह बात भी सही है कि आबादी के बढ़ने के साथ साथ ट्रैफिक के बढ़ने के साथ-साथ असुविधाएं भी महसूस की जा रही हैं। इसी लिए सात फ्लाईओवर्स जिनको आइडेंटीफाई किया था नेशनल ट्रैफिक प्लानिंग एण्ड आटोमेशन सेंटर ने इनको हमने एक्सपेडाइट करके जल्द से जल्द बनवाने की कोशिश की। ताकि एशियाड की नीड्स को केटर करें, और प्लान्स तथा प्रोपोजल्स भी हैं जो डिफरेंट स्टेजेज पर इन्वेस्टीगेशन में हैं। लेकिन जनाबेवाला, आप जानते हैं कि इन फ्लाईओवर्स के कांस्ट्रक्शन आदि के सारे कामों का ताल्लुक रिसोर्सेज से है। जैसे-जैसे रिसोर्सेज होते जायेंगे हम उन रिसोर्सेज के मुताबिक फ्लाईओवर्स के निर्माण की कोशिश, यातायात की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए करते जायेंगे। फ्लाईओवर्स भी बनायेंगे और ओवर-ब्रिजेज भी बनाएंगे। यह जो बताया कि दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के तीन प्रोपोजल्स हैं तो उसमें एक तो सैंक्शन हो गया है और दो एडवांस स्टेजेज में हैं प्लानिंग की, इसके अलावा एक दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से है ब्रिज नं० 22 के लिए ये प्रोपोजल्स हैं। इसके अलावा और भी दूसरे प्रोपोजल्स हैं जो इनीशियल स्टेजेज आफ इन्वेस्टीगेशन में हैं। हम पूरी तौर पर उन जरूरतों से आगाह है और उसकी तरफ हमारी पूरी तवज्जह है।

श्री रामानन्द यादव: सभापति जी, जैसा कि मैंने बताया, भारत सरकार के सभी केन्द्रीय दफ्तर इसी जगह खुलते हैं। चाहे माइनिंग बंगाल में, उड़ीसा में, बिहार में, कर्नाटक में, आंध्र में या और कहीं क्यों न हो, वह दफ्तर वहां नहीं खुलेंगे। हम लोग देखते हैं कि स्टील की अधिकांश मिल्स की लोकेशन्स बंगाल, बिहार और उड़ीसा में हैं और केवल एक भिलाई में इस साइड में है तो भी स्टील का दफ्तर यहां दिल्ली में है। भारत सरकार के कैबिनेट ने निर्णय किया था कि सेल का दफ्तर

रांची में खुलेगा । उसके लिए जमीन एक्वायर कर ली गई। घर बनने की बात हो गई लेकिन अब वह न करके दिल्ली में ही उसका दफ्तर जोर जबरदस्ती के साथ बनाया गया है और यहां रख दिया गया है । क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि रोड बनाने के अलावा यह भी एक तरीका है कि दिल्ली के जो बड़े-बड़े दफ्तर हैं जिनका सम्बन्ध दिल्ली से नहीं है बल्कि बाहर से है । क्योंकि सभी दफ्तरों के लोग, बड़े-बड़े अफसरान बाहर जगहों पर रह करके काम करते हैं क्योंकि जहां वे चीजें लोकेटेड हैं वहां से वे एडमिनिस्ट्रेशन ठीक कर सकते हैं । तो कब सरकार उन दफ्तरों को अपने काम के स्थानों पर ट्रांसफर कर देगी ताकि दिल्ली की आबादी कुछ कम हो जाये, और प्रशासन उन औद्योगिक प्रतिष्ठानों का ठीक हो सके ।

श्री जैड० आर० अन्सारी : जनाबेवाला, मैं तो आपकी मदद का तालिब हूं ।

श्री सभापति : मैं क्या मदद करूं । सारे दफ्तर हटा दीजिए, पार्लियामेंट को भी हटा दीजिए ।

श्री जैड०आर० अन्सारी : यह सवाल न तो मेरे अख्तियार में है और न मेरे सवाल से सम्बन्धित है ।

श्री रामानन्द यादव : आप बनाने की इजाजत देते हैं । क्योंकि बिना आपकी इजाजत के दफ्तर का कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं । आपके डी० डी० ए० को सैंक्शन करना होगा, अन्य दूसरे विभागों को सैंक्शन करना होगा ।

SHRI SHANTI G. PATEL: The increase in the population of Delhi up to a certain point is inevitable. What is necessary is an efficient urban transport system. And this system includes, besides flyovers and roads, also the system of vehicles which can be used by the public in good number. I am referring to the public transport system, particularly the bus system in the city of Delhi which is the worst that we have come across in any city in this country. Will the Minister take steps to improve this particular bus transport system so that many people can travel at one time, instead of making improvements to roads or building flyovers which will essentially help, in my submission, the private driven traffic. What the Government is required to do is to look after a transport system which will be faster, massive and cheap and this could only be achieved by improving the transport system. Therefore, will the Minister lay more emphasis on development of an efficient transport system, particularly the bus transport system of Delhi. by providing more buses and giving other incentives?

SHRI Z. R. ANSARI: I think the question does not arise out of the main question.

DR. SHANTI G. PATEL: How does it not arise? The Minister says that he has less money for flyovers. His approach should be to provide a mass transport system.

MR. CHAIRMAN: The question is about construction of flyovers and you are wanting more buses. You see today's paper. More accidents will take place.

DR. SHANTI G. PATEL: Even in western cities, they are going for public transport system.

MR. CHAIRMAN: I do not think the question does arise.

श्री सदाशिव बागाईतकर : मैं आपके द्वारा मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि जो बहुत उचित बात सम्मानीय श्री रामानन्द यादव जी ने कही कि क्या यह सरकार का निर्णय नहीं है कि दिल्ली से

भीड़ हटाने के तौर पर और डीकन्जेशन करने के लिए अलग-अलग मंत्रालय और उनसे सम्बन्धित जो सारे दफ्तर हैं, उन सभी का केन्द्रीयकरण यहां न किया जाए, यह सरकार की नीति है या नहीं ? और अगर यह घोषित नीति है, तो इस पर अमल क्यों नहीं किया जा रहा है और फ्लाई-ओवर और ट्रांसपोर्ट की जो बातें आपने कहीं, उन्होंने कहा कि इस सवाल से सम्बन्धित नहीं हैं ?

एक सवाल मैं उनसे जरूर पूछना चाहूंगा कि क्या सरकार कम से कम दिल्ली में इस बात पर विचार करेगी कि कुछ ऐसी सड़कें, वह बिल्कुल खाली रखे, जहां कार का आना-जाना मना किया जाए ? मैं उम्मीद करता हूं कि मंत्री जी को इस बात का पता होगा कि लंदन और टोकियो जैसे शहरों में भी खाली पेडेस्ट्रियंस के लिए, ट्रैफिक के लिए रास्ते रखे गये हैं, जहां किसी का कार नहीं जाती है । क्या ऐसा भी सोचना उन्होंने कभी मुनासिब समझा है ?

श्री जेड० आर० अंसारी : माननीय सदस्य ने जो सवाल किया है, वह ट्रैफिक कण्ट्रोल और ट्रैफिक डिसिप्लिन पदा करने से ताल्लुक रखता है और यह जो मेन सवाल है, यह फ्लाईओवर्स के बारे में है ।

श्री सदाशिव बागाईतकर : आप फ्लाईओवर किस लिए बना रहे हैं ? ट्रैफिक में डिसिप्लिन लाने की बात नहीं है, तो फ्लाईओवर किस लिए बना रहे हैं ? कमाल है ।

SHRI Z. R. ANSARI: Sir, I seek your protection.

श्री सभापति : मिनिस्टर साहब, सीधा सा जवाब था कि अच्छा इस पर गौर किया जाएगा और किस्सा खत्म हो जाता । आप काहे को झगड़े में पड़ते । आखिरी सवाल ।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : आपने जवाब में कहा है कि जखीरा के पास रोहतक रोड पर पुल बनेगा । बड़ी सही बात है । मैं पूछना चाहता हूं कि इस जखीरे के पुल की योजना कब प्रारम्भ की गई थी, क्योंकि दस-पन्द्रह साल से मुझे मालूम है वहां की पब्लिक के लोग मेमोरेण्डम देते रहे हैं ? तो यह योजना कब प्रारम्भ की गई थी और यह अब पूरी कब होगी ? और इस पर कितना पैसा लगेगा, डी० डी० ए० कितना लगाएगा, आप कितना लगायेंगे, कारपोरेशन कितना लगाएगी, जो-जो डिपार्टमेंट हैं, वह कितना-कितना पैसा लगायेंगे ?

तो नम्बर एक, योजना कब बनी, प्रारम्भ कब हुई ? इस पर पैसा कौन-कौन लगाएगा, और यह खत्म कब होगी ?

SHRI VIJAY K. BHASKARA REDDY: The flyover in Zakhira is in the final stage. Tenders have been called for and 17th was the last date. It will be finalised soon and the work will start.

SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR: When?

SHRI K. VIJAYA BHASKARA REDDY: Long back it has started. It has a big history. Tenders have been called for.

SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR: That I understand. What I am requesting you to tell is when the Delhi Administration or the Corporation sent this proposal because my apprehension is, Sir, that it was kept in abeyance because a non-Congress (I) was in authority in Delhi and now, when they have come to power, they are going ahead with this. That is what I am asking.

MR. CHAIRMAN: That is all right.

SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR: Let him say that, Sir. It is a fact.

MR. CHAIRMAN: Are you making it political?

SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR: I am not making it political. I am just asking him when it was started and why it was done earlier.

MR. CHAIRMAN: It is all over now.

SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR: He says it was started ten or fifteen years back. But the Central Government did not do anything. It is not politics. So, my apprehension is...

SHRI K. VIJAYA BHASKARA REDDY: Whatever he may say, we take pride in sanctioning it and we are going to start it soon.

SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR: It should have been initiated earlier. But you cut it short. (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: All right. Next Question. Question No. 282.

*282. [*The questioners (Shri V. R. Krishnan and Shri B. C. Pattanayak) were absent. For answer* vide **Col. 36 to 38 infra.**]

श्री जगन्नाथ राव जोशी : 283 के साथ 287 को जोड़ा जा सकता है । यह सवाल नस्ल सुधारने के लिए है, लेकिन जब तक हत्या पर पूरा प्रतिबन्ध नहीं होगा, न दूध के उत्पादन को बढ़ाने की कोशिश की जा सकेगी और न ही सारे उपाय कारगर हो सकेंगे ।

SHRI INDRADEEP SINHA: Sir, questions No. 283 and No. 287 are different.

MR. CHAIRMAN: All right. मैं देखता हूं कि 287 इसके साथ आता है या नहीं ।
Now, we go to question No. 283.

Improvements in the milch cattle breed

*283. SHRI GHAN SHYAM SINGH:†
SHRI BISHAMBHAR NATH PANDE:

Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether the efforts of the National Dairy Development Board and the Indian Dairy Corporation have resulted in the genetic improvement of India's cattle wealth;

(b) whether it has helped in the increase in milk production during the last five years;

(c) to what extent the Frozen Semen Technology of artificial insemination from pedigree stock has helped in the improvement of the national milch herd covering both cows and buffaloes; and

(d) what steps the National Dairy Development Board has taken to ease the problem of fodder for cattle?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI YOGENDRA MAKWANA): (a) to (d) A statement is laid on the Table of the Sabha.

Statement

(a) and (b) Yes, Sir.

(c) Frozen semen technology is superior to the use of liquid semen for the following reasons:—

(1) Increase in the rate of conception.

(2) Better utilisation of superior pedigreed bulls.

(3) Preservation of semen for longer periods.

†The question was actually asked on the floor of the House by Shri Ghanshyam Singh.